दैनिक दबंग दुनिया, भोपाल

16 MAY 2015

बचे साढ़े तीन साल, सरकार-नौकरशाही की बढ़ेगी चाल

भोपाल। मप्र के विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोर टीम बहुत जल्द अपनी रणनीतियों में व्यापक बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह पिछले साल के अधूरे विकास कार्यों एवं वे विभागीय घोषणाएं हैं, जिसकी वजह से सरकार को जनता और पार्टी विधायकों की नाराजगी से दो-चार होना पड़ रहा है। कोर टीम में शामिल आईएएस अफसरों की इस बारे में मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा भी हो चुकी है और अगले एक साल का 'लाइन ऑफ एक्शन' बना लिया गया है। नतीजन सरकार के बचे हुए साढ़े तीन साल के कार्यकाल में डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव लाजमी तौर पर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने चुनिंदा आईएएस अफसरों वाली कोर टीम को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि वे प्रशासनिक कसावट लाकर सिस्टम को दुरुस्त करें, ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ अतिशीघ्र मिले। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता राज्य की कानून व्यवस्था,

विशेष

विजय शुक्ला

अंटोनी डिसा

एस.के मिश्रा

इकबाल सिंह बैस

सुरेन्द्र सिंह

मनोज श्रीवास्तव

हरिरंजन राव

बेटियों की सुरक्षा, बिजली और किसान हैं। लिहाजा इन मुद्दों पर आए दिन बैठकों का सिलसिला मंत्रालय से लेकर सीएम हाउस तक तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज की एक और बड़ी चिंता गुड गवर्नेंस को लेकर है, क्योंकि सरकार की छवि पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। जिलों में तैनात अफसर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी का भार भी सरकार पर पड़ रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने थोक में पुलिस विभाग में अफसरों के तबादले का आदेश शुक्रवार को जारी किया। इसके साथ ही कलेक्टरों की नई पदस्थापना का दौर चालू है। किसानों को कुदरत का कहर झेलना पड़ा, इसलिए गेहूं खरीदी का काम अच्छे से हो। इस बात को लेकर भी विभागीय तैयारियां चल रही है। गौरतलब है कि 14 दिसम्बर 2013 को शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट 2018 जारी किया था। उसमें कई सेक्टरों में तेजी से कार्य करने के लक्ष्य तय किए गए मगर मुख्यमंत्री की सकारात्मक मंशा को नौकरशाही की सुस्ती ने निर्धारित समय के हिसाब से काम नहीं किया। नतीजन सरकार के बचे हुए साढ़े तीन साल और कुछ दिनों के कार्यकाल में डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव लाजमी तौर पर बढ़ गया है।

इन सेक्टरों के अवसर व चुनौतियां का है उल्लेख

डॉक्यूमेंट में कृषि को शीर्ष पर रखा गया है। इसके बाद उच्च शिक्षा, मेडिकल व टेक्निकल एजुकेशन। फिर उभरते हुए क्षेत्र की श्रेणी में बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी व नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों, वन, खनिज, पर्यावरण, टूरिज्म को रखा जाएगा। आधारभूत संरचनाओं को मजबूती देने के लिए अर्बन, रोड और पॉवर को भी अहम स्थान दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अवसर व चुनौतियों पर आधारित है।

बदलाव का जिम्मा इन पर...

सरकार अपनी रणनीति में जो बड़े बदलाव करने जा रही है। उसकी जिम्मेदारी प्रमुख रूप से 9 अफसरों पर होगी, क्योंकि समन्वय के साथ क्रियान्वन का काम इनकी देख-रेख में होगा।

इन अफसरों की बढ़ी जिम्मेदारियां

- अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव
- सुरेंद्र सिंह, डीजीपी ।
- इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव सीएम।
- एसके मिश्रा, प्रमुख सचिव सीएम एवं कमिश्नर जनसंपर्क।
- मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास।
- विवेक अग्रवाल, सचिव सीएम एवं कमिश्नर नगरीय प्रशासन।
- मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव उद्योग।
- राकेश श्रीवास्तव, आयुक्त आबकारी।
- अरुण भट्ट, सचिव मुख्यमंत्री